

गुरप्रीत कौर बनाम भारत संघ और अन्य (एम. एम. पुंछी, जे.

गलत परिसर में। पूरी प्रक्रिया और पहले और दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा दिखाया गया रवैया अप्रिय है जो गंभीर आलोचना की मांग करता है। लेकिन हमारे पास जो पद है उसका बड़प्पन हमें रोकता है।

(१) उपरोक्त कारणों से, विद्वान एकल न्यायाधीश के 21 नवंबर, 1988 के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को लोक प्रशासन में व्याख्याता के दूसरे पद के खिलाफ अपीलकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके लिए उसे चयन समिति द्वारा विधिवत चुना गया था और सिंडिकेट द्वारा उसके चयन को विधिवत अनुमोदित किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 3 के चयन और नियुक्ति में गड़बड़ी नहीं की गई है। तदनुसार अपील को अनुमति दी जाती है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

पी.सी.जी.

एम. एम. पुंछी और ए. एल. बहरी, जेजे. के सामने

गुरप्रीत कौर, —याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य, - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1989 का 5497

3 अक्टूबर, 1989।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - याचिकाकर्ता आवंटित: हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्लैट - निर्धारित तिथि की समाप्ति के बाद किया गया 15 प्रतिशत जमा - बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि - बाद की किस्तें भी स्वीकार की जाती हैं - बोर्ड द्वारा कोई राशि वापस नहीं की जाती है - देरी से जमा के आधार पर प्लॉट को रद्द करना - यदि अनुमति है।

और रूपयदि आवंटन रद्द कर दिया जाता है, तो बोर्ड समझौते के खंड 19 में प्रदान की गई राशि को तुरंत वापस करने के लिए बाध्य था। स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई रिफंड नहीं भेजा गया। बल्कि इसके विपरीत, समय-समय पर, किस्तों को स्वीकार किया जा रहा था। इस स्थिति में, हाउसिंग बोर्ड के लिए यह कहने में बहुत देर हो चुकी है कि आवंटन रद्द माना गया था। बल्कि हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन को रद्द नहीं माना जा सकता है। (पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड को उसके अवलोकन के बाद आगे भेजा जाए, निम्नलिखित राहत दी जा सकती है:-

(एक) प्रतिवादियों को आवासीय इकाई सं 2008 का कब्जा सौंपने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी करें। 3058 में से

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

चंडीगढ़ के सेक्टर 41-डी में एलआईजी/एफ श्रेणी में याचिकाकर्ता को आवास इकाई की बरकरार स्थिति के साथ रखा गया है;

- (ii) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कब्जा कार्यालय को हटाने के लिए प्रतिवादियों को जारी किया गया आदेश जारी किया गया है। नहीं/सेक्टर 41-डी, चंडीगढ़ में एलआईजी/एफ श्रेणी की धारा 3058 और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पूरी अवधि अर्थात् 10,000 रुपये की प्रारंभिक जमा की तारीख से किराए या नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया जाए। 12723. जब याचिकाकर्ता अपने कब्जे का हकदार था:
- (3) कोई अन्य राहत, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है, उसे भी दिया जाए;
- (4) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना और प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करना बंद किया जाए;
- (5) याचिकाकर्ता को रिट याचिका की लागत भी दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम. एल. स्नरमा।

अशोक भान, सीनियर एडवोकेट, आरके गर्ग, एडवोकेट, के साथ, के लिए प्रतिवादी।

आर. एस. मोंगिया. जे. एस. साधी के साथ सीनियर एडवोकेट। एडवोकेट। उत्तरदाता संख्या के लिए। 2.

निर्णय

एम. एम. पुंछी, J.

- (1) याचिकाकर्ता को 12 मार्च 1987 को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक टोपी आवंटित की गई थी। समझौते के संदर्भ में, उसे पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर आवंटन को स्वीकार या अस्वीकार करना आवश्यक था। स्वीकृति के मामले में, उसे 12,723 रुपये की राशि और शेष विनियमित किस्तों को जमा करने की आवश्यकता थी। समझौते के खंड 3 में प्रावधान किया गया था कि यदि निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया गया था तो आवंटन रद्द माना जाएगा और जमा राशि को जब्त करने के बाद वापस कर दिया जाएगा जैसा कि उसके खंड 19 में प्रावधान किया गया है। जब्त 10 प्रतिशत की प्रारंभिक जमा राशि से होनी थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेज जमा करने थे। याचिकाकर्ता ने 29 अप्रैल को देर से भुगतान किया। 1989 जिसे बोर्ड द्वारा काउंटर पर स्वीकार किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 2 में वर्णित विभिन्न भुगतान किए, जिन्हें बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया। अब बोर्ड ने समझौते के खंड 3 को यह कहते हुए लागू किया है कि चूंकि 15 प्रतिशत, यानी 12,723 रुपये देर से जमा किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता का आवंटन रद्द माना जाता है।

- (2) समझौते का खंड 4 दिलचस्प पठन बनाता है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति खंड 3 में निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि बढ़ा सकता है। समय आगे बढ़ाया जा सकता है- अधिकतम तीन महीने के अधीन। देरी से भुगतान पर ब्याज लगाया जाता है और कुछ मामलों में दंडात्मक ब्याज भी अनुमेय है।
- (3) इन परिस्थितियों में हाउसिंग बोर्ड के विद्वान वकील की दलील। इसके खंड 3 की शर्तें समझौता पूर्ण है, यह सही नहीं है। यदि दी गई परिस्थितियों में, खंड 4 के तहत समय बढ़ाया जा सकता है, तो खंड 3 की कठोरता पूर्ण नहीं है। इसके अलावा, आवंटन रद्द होने की स्थिति में बोर्ड समझौते के खंड 19 में की गई राशि को तुरंत वापस करने के लिए बाध्य था। स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई रिफंड नहीं भेजा गया। इसके विपरीत, समय-समय पर, किस्तों को स्वीकार किया जा रहा था। इस स्थिति में, हाउसिंग बोर्ड के लिए यह कहने में बहुत देर हो चुकी है कि आवंटन को रद्द माना गया था। हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन को रद्द नहीं माना जा सकता है।
- (4) बोर्ड के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज भेजने के निर्देशों का पालन नहीं किया है और जो भेजे गए हैं वे संदिग्ध पाए गए हैं। बोर्ड द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। यदि यह आवंटन रद्द करने का मामला है, तो प्रतिवादी बोर्ड को याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करनी होगी। उस हिस्से पर, हम यह नहीं सुनाते हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी उचित कार्रवाई करने के लिए बोर्ड पर छोड़ देते हैं जैसा कि कानून के लिए जाना जाता है।
- (5) पूर्वगामी कारणों से, हम आंशिक रूप से इस याचिका को स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ता के आवंटन को लागू किया गया है, भले ही देरी से भुगतान किया गया हो, जिससे बोर्ड के लिए अन्य प्रश्न खुले रह गए हैं। हालांकि, बोर्ड इसे बढ़ा सकता है। देरी से भुगतान के लिए ब्याज की मांग। बोर्ड के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता से इस संबंध में कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। कोई कीमत नहीं।

. पी. सी. जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी